



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरबार, १५ अक्टूबर, १९९२/२३ आश्विन, १९१४

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, १ अक्टूबर, १९९२

संख्या : एफ० डी० एस० ए० (४) ५/८७.—हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, १९८३ (१९८३ का १७) की धारा १५-क की उप-धारा (४) का खण्ड (ख) (II) लोक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को कानूनी पद के कृत्यों के पालन और कर्तव्यों के निर्वहन की अनुज्ञा देता है ;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि प्रधान, हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग के कर्तव्य और कृत्य लोक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाएं, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६ (१९८६ का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक ६८) के अधीन एक कानूनी पद है ;

और हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, १९८३ की धारा १५-क की उप-धारा (४) के अधीन अथवा अपेक्षित लोक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश की पूर्व सम्मति प्राप्त कर ली गई है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, १९८८ के नियम १४ के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६ की धारा १६ की उप-धारा (१) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की सम संख्यांक अधिसूचना,

तारीख 21 जून, 1991 के अधिकरण में सेवानिवृत्त न्यायामूर्ति श्री आर० बी० मिश्रा, लोक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त, प्रधान, हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग (राज्य आयोग के नाम से ज्ञात) के रूप में तुरन्त नियुक्त करते हैं।

[Authoritative English text of this Department notification No. FDS. A (4) 5/87, dated 1-10-1992 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st October, 1992

No. FDS. A (4)5/87.—Whereas clause (b) (ii) of sub-section (4) of section 15-A of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983) permit the Lokayukta, Himachal Pradesh to perform the functions and to discharge the duties of a statutory office;

And whereas the Governor, Himachal Pradesh satisfied that Lokayukta, Himachal Pradesh may be entrusted the duties and functions of President, Himachal Pradesh Consumer Disputes Redressal Commission which is a statutory office under the Consumer Protection Act, 1986 (Central Act No. 68 of 1986);

And whereas, the prior consent of the Lokayukta, Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of section 15-A of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 has been obtained.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1)(a) of section 16 of the Consumer Protection Act, 1986 read with rule 14 of the Himachal Pradesh Consumer Protection Rules, 1988 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh in supersession of this department notification of even number, dated 21st June, 1991, is pleased to appoint Mr. Justice R. B. Misra (Retired), Lokayukta, Himachal Pradesh as President, Himachal Pradesh Consumer Disputes Redressal Commission (known as State Commission) in addition to his own duties with immediate effect.

By order,  
A. N. VIDYARTHI,  
Financial Commissioner-cum-Secretary.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 अक्टूबर, 1992

संख्या : रैव० 2 एफ(6)-7/80-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश होटलिंगज (कनसोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ फ्रैगमेंटेशन) ऐक्ट, 1971 की धारा 21 की उप-धारा (4) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश होटलिंगज (कनसोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ फ्रैगमेंटेशन) रूलज, 1971 के नियम 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से बिलासपुर, मण्डी, सोलन, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा के बरिष्ठ उप-न्यायाधीशों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में उन मामलों में जहाँ संवन्धित व्यक्तियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 21 (1) क अधीन दाखिल किए गए आक्षेप हक का प्रश्न अन्तर्बलित करते हैं, पंचाट (अवार्ड) देने हेतु "मध्यस्थ" नियुक्त करते हैं।

2. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुनः निदेश देते हैं कि माध्यस्थता फीस प्रत्येक एकल मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से नियत की जाएगी।

[Authoritative English text of this Department notification No. Rev. 2F(6)-7/80-II, dated 3-10-92, as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## REVENUE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd October, 1992

No. Rev. 2F(6)-7/80-II.—In exercise of the powers conferred by rule 24 of the Himachal Pradesh Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Rules, 1973 read with sub-section (4) of section 21 of the Himachal Pradesh Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act, 1971, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, is pleased to appoint the Senior Sub-Judges, Bilaspur, Mandi, Solan, Una, Hamirpur and Kangra as 'Arbitrators' within their respective jurisdiction to make an award in cases where objections filed by concerned persons under section 21(1) of the said Act involves a question of title.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to direct that the arbitration fee shall be fixed in consultation with the High Court of Himachal Pradesh in each individual case.

By order  
O. P. YADAV,  
F. C.-cum-Secretary.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 अक्तूबर, 1992

संख्या: 4-13/83-श्रम-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश असाधारण में तारीख 15-6-1991 को पूर्व प्रकाशित इस विभाग की सप्तसंख्यांक अधिसूचना तारीख 3-6-91 द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग-1 के अधीन (1) कास्टिंग उद्योगों, (2) चमड़ा उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को एक प्रकार के नियोजन के रूप में जोड़ते हैं।

[Authoritative English Text of this Government notification No. 4-13/83-Shram-II dated 8th October, 1992 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th October, 1992

No. 4-13/83-Shram-II.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to include the employments in (1) Casting Industries, (2) Leather Industries and (3) Electronics Industries

as one of the employments under Part-I to the Schedule of the Minimum Wages Act, 1948 after previous publication in the Himachal Pradesh Extraordinary Rajpatra dated 15-6-91 vide this Department notification of even number, dated 3-6-1991.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.

लोक सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 अक्टूबर, 1992

संख्या: पब-एफ(4)-12/86.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल ध्याल, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि ली जाती अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का प्रथम अधिनियम) की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत तथा इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यांक दिनांक 16-7-92/17-7-92 को अधिक्रमण करते हुए जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरणी

जिला : कांगड़ा

तहसील : धर्मशाला

मुद्दा 1	मौजा 2	खसरा नं० 3	रकबा हक्टेधरों में		
			4	5	6
ध्याल	धर्मशाला	544	0	22	05
		544/1	0	19	73
		544/2	0	21	98
		किता .. 3	0	63	76

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

आयुक्त एवं सचिव।